मैच के बहाने क्रिकेट व्यवसाय पर विधायक की नज़र

फ़रीदाबाद (म.मो.) नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम को दुर्दशा से उबारने की आड़ में स्थानीय विधायक विपुल गोयल ने वहां एक नुमायशी मैच का आयोजन किया। इसे खिलाड़ियों के बज़ाय बॉलीवुड के नाचने गाने वालों और भोजपुरी गायक एवं भाजपा सांसद मनोज तिवारी की टीमों ने खेला। वास्तव में यह क्रिकेट कम और ड्रामेबाज़ी अधिक था। आयोजन का मकसद शहर में क्रिकेट व इसके स्टेडियम को पुनर्जीवित करना बताया गया था।

काले-पीले व्यापार के खिलाड़ी विपुल गोयल का क्रिकेट से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन इस खेल में आज दुनिया के किसी भी खेल से कहीं अधिक पैसा है। इसलिये देश के अनेकों राजनेता एवं उनके लग्गुए-भग्गुए या तो इससे चिपके हुए हैं या चिपकने की जुगत में हैं। हरियाणा में इस खेल के व्यापार पर बंसीलाल के पुत्र रणबीर महेन्द्रा का पूर्णरूप से न केवल एकाधिकार है बल्कि अपने मरने के बाद का भी इन्तज़ाम उन्होंने कर छोड़ा है। इसलिये फिलहाल फ़रीदाबाद में क्रिकेट को मात्र एक खेल की तरह तो खेला जा सकता है परन्तु व्यवसाय की तरह नहीं। रही बात स्टेडियम की, तो वह एक सरकारी संपत्ति है सार्वजनिक प्रयोग के लिये जिसका उचित रख-रखाव करना सरकार का दायित्व है।

इस मैच की तैयारी के लिए सरकार ने अपना यह दायित्व निभाया भी लेकिन इसके लिये विपुल के इस नुमायशी ड्रामे की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिये थी। इसके लिये मुख्यमंत्री को तो आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिये थी। जितना खर्च सरकार के विभिन्न विभागों ने इस काम पर कर दिया उससे कई गुणा खर्च तो इस नुमायशी ड्रामे पर हो गया। इससे क्रिकेट और इस शहर का तो कोई भला होता नज़र नहीं आ रहा। हां इस ड्रामेबाज़ी के चलते विपुल व उनके भाई-भतीजे जरूर कई दिनों तक अखबारो में छपते रहे।

एक और गौरतलब बात यह भी है कि विधायक महोदय का ध्यान उन अस्पतालों व स्कूलों की ओर न जाकर जिनसे शहर के गरीबों का वास्ता पड़ता है, केवल क्रिकेट व इसके स्टेडियम की ओर ही गया है। तरह-तरह की समस्याओं से जूझ रही शहर की जनता को आखिर कब तक इस तरह के ड्रामे से बहलायेंगे विधायक महोदय? शायद जनता के मतलब के काम उनके बस के ही नहीं।

कलम रो पड़ी आज मेरी

मां काश आज मैं स्कूल ना जाता शायद तुम्हें फ़िर से देख पाता
तेरी आवाज सुनने को कान तरस रहे हैं
देखो ना मां बारूदों के गोले बरस रहे हैं।
सारे बच्चे अपनी-अपनी मां को पुकार रहे हैं,
मां ये लोग क्यों हमें मार रहे हैं टिफिन में दी तुम्हारी रोटी
नहीं खाई है। मां आज गोलियों ने मेरी भूख मिटाई है।
पापा से कहना अब मुझे स्कूल लेने ना आये
देख नहीं पाऊंगा तुम्हें मेरा जनाजा उठाये।
मेरे जाने से अपना हौंसला मत खोना मां मुझसे बिछुड़कर
तुम मत रोना मेरे खिलौने, मेरी किताबें,
मेरा बस्ता, जानता हूं तरी आंखे देखती रहेंगीं,
रोज मेरा रास्ता, भईया से कहना, उसका साथी रूठ गया है
बचपन का हमारा साथ, छूट गया है। आपा से कहना मेरे लिये,
आंसू ना बहाये रोज़ मेरी तस्वीर को छोटा सा फूल चढाये
तेरी यादों में ख्वाबों में जिक्र में रह जाऊंगा, मां अब मैं कभी
वापस नहीं आऊंगा

साभार फेसबुक

मोदी और गणतंत्र दिवस

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आ रहे हैं। पूंजीवादी मीडिया, भारत सरकार सभी बहुत खुश हैं। उनकी खुशी कुछ उसी तरह की है जैसी किसी सड़क छाप गुंडे को शहर मे डॉन के अपने घर आने पर होती हे। खुशी दो गुनी तब हो गयी जब डॉन ने पड़ोसी पाकिस्तान के आमंत्रण को ठुकरा दिया।

ओबामा अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि हैं। वह शांति नोबेल के विजेता हैं। इससे किसी को भी सहज उम्मीद होनी चाहिए कि उन्होंने शांति के लिये कुछ विशेष किया होगा। पर अफ़सोस ओबामा ने अपने जीवन में शांति लाने नहीं शांति छीनने का एक भी मौका नहीं गंवाया। बंदूकों के दम पर तो उन्होंने दुनिया के गरीबों को कुचला ही साथ ही पूंजी के दम पर भी ग़रीबों का निवाला छीनने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। इराक, अफ़गानिस्तान, लीबिया, सीरिया, अफ्रीका, पाकिस्तान तक को इनके टैंकरों, जहाजों, द्रोणों ने कत्लगाह में तब्दील कर डाला। ओबामा की शांति का मतलब शायद मौत के बाद छाने वाले सन्नाटे से है तो इस लिहाज से ओबामा शांति का सबसे बड़ा 'पुजारी' है।

ओबामा की काबलियत हथियारों के दम पर मौतें देने में ही नहीं, बल्कि अपने देश के थैलीशाहों की पूंजी के दम पर भी दुनिया के मेहनतकशों को ठंडी मौतों की ओर धकेलने में है। रीगन, थैचर के जमाने से शुरू हुई नवउदारवादी नीतियों को अमेरिका के साथ-साथ पूरी दुनिया के शासकों से लागू करवाने के लिए ओबामा ने दिन-रात एक कर दिया। इसके लिये अपने देश के मज़दूरों को मिल रही सुविधाओं को मज़दूरों से छीन पूंजीपतियों पर लुटाना शुरू करने में वे नंबर एक हैं। दुनिया के शासकों को भी वे मज़दूरों-मेहनतकशों को मिल रही सुविधाएं छीनने को मजबूर करते हैं। जितने लोग गोलियों-बमों से मारे, उससे ज्यादा इसने अपनी पूंजी की ताकत से मार डाले।

ओबामा ने 'लोकतंत्र और आतंकवाद' को ऐसा जुमला बना दिया कि सब आश्चर्यचकित हो गये। अमेरिका जब चुनी गयी लोकतांत्रिक सरकार गिराता है तब वह आतंकवाद से लड़ रहा होता है जब वह आतंकवाद के संगठन रोप रहा होता है तो वह लोकतंत्र की पौध रोपने की तैयारी करता है। कुल मिलाकर संक्षेप में जो अमेरिका के हिसाब से चले वह लोकतांत्रिक और जो न चले वह आतंकवादी।

ओबामा का पेट दुनियाभर के मेहनतकशों के खून से नहीं भरता बल्कि वे अपने देश के मज़दूरों का खून चूसने में नंबर एक हैं। उसके चंद वर्षों के शासन में मज़दूरों के वेतन कटौती, छंटनी, बेकारी, सरकारी सुविधाएं छीनने के जो तांडव देखे वे अभूतपूर्व हैं।

उपरोक्त गुण सम्पन्न ओबामा अगर अगले वर्ष भारत आयेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की खुशी छिपाये नहीं छिपेगी। आखिर महत्वाकांक्षी मोदी भी अपने कर्मों से ओबामा से थोड़ा ही पीछे हैं। ओबामा से आगे निकलने की उनकी इच्छा भी लगातार जोर मार रही है। हालांकि अभी दूर-दूर तक इसकी संभावना नहीं है फ़िर भी दोनों की खून की प्यास बड़ी तगड़ी है।

मोदी ने दो ही मुलाकातों में आखिर क्या ऐसा कर डाला कि ओबामा उन पर मेहरबान हो उठे? इसका जवाब मोदी के 6 माह के कार्यकाल में पूंजीपतियों के पक्ष में लिये गये निर्णयों में है। साम्राज्यवादी पूंजी को देश में खुली छूट, सस्ती जमीन, बिजली का भरोसा, खनिज संसाधनों तक बेरोकटोक पहुंच का वायदा, मज़दूरों के साथ मनमर्जी करने की छूट आदि कुछ कारण हैं जिससे देशी के साथ-साथ विदेशी पूंजी भी मंत्रमुग्ध है।पर इसके साथ-साथ खाद्य सब्सिडी के मसले पर डब्ल्यू.टी. ओ. में फंसे विवाद पर मोदी-ओबामा के बीच बनी सहमति ने ओबामा का दिल जीत लिया। मोदी ने ओबामा से यह समझौता कर लिया कि 2017 तक विकासशील देशों को खाद्य सब्सिडी की छूट रहेगी। इस समय तक वे इस समस्या का हल निकाल लेंगे। इसके साथ ही व्यापार से जुड़े ट्रेड फैसिलेशन एग्रीमेंट (टी एफ ए) पर भारत सहमत हो गया है। इसके तहत सीमा कर की दरें अब डब्ल्यू.टी.ओ. की सहमति से तय होंगी।

ये दोनों ही मसलें वर्षों से डब्लू.टी.ओ. में अटके थे। खाद्य सब्सिडी व व्यापार दोनों मसलों पर विकासशील देश भारत, दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा, बोलिविया, बेनेजुएला, जिम्बाम्बे आदि अड़ गये थे परिणामस्वरूप विश्व व्यापार संगठन का एजेंडा आगे नहीं बढ पा रहा था। विकसित साम्राज्यवादी देश चाहते थे कि ग़रीब मुल्क अपने यहां खाद्यान्न सब्सिडी को विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अनुरूप नीचे ले आयें ताकि साम्राज्यवादी खाद्यान्न कम्पनियां अपना अनाज इन देशों में पाट सकें। साथ ही साम्राज्यवादी चाहते थे कि गरीब देश सीमा कर नीचे लाकर साम्राज्यवादी मालों को गरीब मुल्कों के बाजारों तक आसान बना दें। परंतु गरीब मुल्कों के शासक वर्ग इस सबके लिये अपनी जनता के दबाव व देशी पूंजीपतियों को मिलनेवाली प्रतियोगिता के मद्देनज़र तैयार नहीं थे।

पर अब मोदी को दोनों मसलों पर राज़ी कर साम्राज्यवादी एक बड़ा दांव जीतने में सफल हो चुके हैं। फ़िलहाल तीन वर्षों के लिये खाद्य सब्सिडी के लिए मिली छूट को भारत सरकार अपनी जीत के बतौर प्रचारित कर रही है पर वे यह बात छिपा रहे हैं कि ये समझौता अगले तीन वर्षों में खाद्य सब्सिडी बेहद कम करने व अंतत: विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अधीन करने की ओर ले जायेगा।

इस तरह मोदी ने न केवल देश की गरीब जनता को मिल रही खाद्य सब्सिडी को छीनने का सौदा किया बल्कि अब तक सहयोगी रहे अन्य विकासशील देशों से भी अपने साथ से पल्ला झाड़ दिया। जाहिर है ओबामा को खुश होना जरूरी था और इस खुशी को वे भारत यात्रा के द्वारा खुलेआम एलान भी कर रहे हैं।

ओबामा की यात्रा भारतीय राष्ट्रवाद की समापन कथा भी है। भारत के पूंजीपति वर्ग के राष्ट्रवाद में वैसे भी कोई प्रगतिशीलता दशकों पहले भी नहीं बची थी, अब तो यह घोर प्रतिक्रियावाद में तब्दील हो चुका है। भारतीय राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद या सामन्तवाद विरोध में कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं निभायी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शसन के अंत में भारतीय मज़दूरों, किसानों, सैनिकों, नौजवानों और अन्य शोषित-उत्पीड़ित लोग़ों के संघर्ष ही थे। भारत का पूंजीपति व भूस्वामी वर्ग तो जी-हुजूरी को ही अपना मूलमंत्र समझता था। वह आज भी वही कर रहा है।

ओबामा को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाना भारत की जनता का अपमान है। यह भारत के महान शहीदों का भी घोर अपमान है। भारत के पूंजीपति वर्ग को मोदी की कूटनीति पसंद आ सकती है। परंतु भारत की जनता को मोदी की रणनीति क्षुब्ध और क्रोधित ही कर सकती है।

ओबामा-मोदी की ये गलबहियां भारत के मेहनतकशों के लिए खतरनाक हैं। दो आतताइयों का यह मिलन पूंजीपतियों-साम्राज्यवादियों के चेहरों पर रौनक लायेगा पर इस मिलन के जरिये करोड़ों मज़दूर-मेहनतकशों के जीवन में अंधेरा और गहरा जायेगा। इसीलिए ओबामा-मोदी के मिलन पर देशी-विदेशी पूंजीपति ताली पीटेंगे पर मेहनतकश जनता मुटिठ्यां ताने नारे लगायेगी 'ओबामा वापस जाओ'।

-नागरिक

अस्ती इलेक्ट्रोनिक्स के बहाने

वाहनों की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वाशिंग मशीन आदि के इलेक्टिक कन्ट्रोल बोर्ड, मोबाइल फ़ोन के सर्किट बोर्ड, रोबोट्स के कन्ट्रोल आदि का उत्पादन करती अस्ती कारपोरेशन की 6 फैक्ट्रियां जापान में, 2 चीन में, 2 वियतनाम में, और एक फैक्ट्री प्लॉट 399 सेक्टर -8, आई एम टी मानेसर में है। अस्ती के ग्राहकों में सुजुकी, यामाहा, पैनासोनिक, टोयोटा, डेन्सो, कावासाकी, होण्डा, मित्सुबिशी, हिताची, सान्यो, कैनन, सोनी, रोलैण्ड, पुजित्सु, कोस्मो आदि कम्पनियां हैं।

आई एम टी स्थित अस्ती इलेक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री में अक्टूबर 2005 में उत्पादन आरम्भ हुआ। तीन शिफ़्टों में 480 मज़दूर, जिनमें तीन-चौथाई महिला मज़दूर थी। स्थाई मज़दूर 130 थे और ठेकेदारों के जरिये रखे 350 तथा दोनों की तनखायें बहुत कम, 5500-6000 रुपये। जहां स्थाई और अस्थाई में फर्क कम होते हैं वहां मज़दूरों में तालमेल स्वाभाविक तौर पर बढते हैं और फैक्ट्री स्तर पर आज की हालात में वास्तविक मज़दूर संगठन उभरने लगता है। ऐसी स्थिति अस्ती इलेक्ट्रोनिक्स में थी।

ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिये सरकार की फीस पांच रुपये है। टाइपिंग और डाक खर्च सौ-दो सौ-तीन सौ रुपये। फैक्ट्री में रजिस्टर्ड यूनियन का सदस्य बनने के लिये स्थाई मज़दूर होना कानून अनुसार जरूरी है। कैजुअल वरकर और ठेकेदारों के जरिये रखे मज़दूर फैक्ट्री ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हो सकते अगर उस यूनियन का सरकार में रजिस्ट्रेशन है, अथवा रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्थाई और अस्थाई मज़दूरों के तालमेल से उभरते वास्तविक मज़दूर संगठनों को तोड़ने का फेर है यूनियन रजिस्ट्रेशन। इसके लिये कुछ गिरोह काम कर रहे हैं जो यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिये मज़दूरों से दो-तीन-चार-पांच लाख रुपये लेते हैं। यूनियन के रजिस्ट्रेशन से इस-उस चमत्कार की बातें बाबाओं के चमत्कारों जैसी तो हैं ही, यह अधिक खतरनाक भी हैं क्योंकि यह मज़दूरों को कानून-विधान-संविधान के दलदल में भी डालती हैं। स्थाई और अस्थाई मज़दूर के जोड़ों से बनते वास्तविक मज़दूर संगठनों को तोड़ने के लिये रजिस्टर्ड यूनियनें आज सरकारों तथा कम्पनियों के हाथों में एक धारदार औजार हैं। होण्डा में अस्थाई मज़दूरों द्वारा स्थाई को ''पंच एण्ड लंच'' वाले कहना, अस्ती मज़दूरों द्वारा ''परमानेन्ट मज़दूर मुर्दाबाद'' के नारे लगाना आज फैक्ट्रियों में यूनियनों की वास्तविकता की एक झलक है।

अस्ती इलेक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री में यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिये स्थाई और अस्थाई मज़दूरों को इस वर्ष 7 फरवरी को तनखा मिली तब 1000-1000 रुपये प्रति मज़दूर गुपचुप लिये गये। 18 फरवरी को स्थाई तथा अस्थाई मज़दूरों ने मिल कर काम बन्द किया और कम्पनी को 2-3 निकाल रखे मज़दूरों को वापस लेने को बाध्य किया। ऐसे में 7 मार्च को तनखा मिली तब हर मज़दूर से यूनियन ने 500-500 रुपये और लिये। प्रभावित हुये कुछ मज़दूरों ने तो 1000-1500 रुपये अतिरिक्त भी दिये।

अस्ति में यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो गया। स्थाई मज़दूरों से सदस्यता शुल्क लेना। अस्थाई मज़दूरों से पैसे लेना बन्द। अप्रैल में यूनियन ने कम्पनी को मांग-पत्र दिया। स्थाई और अस्थाई की तनखाओं में बराबर बढोतरी की बातें, अस्थाई को स्थाई करने की बातें। अटपटी शिफ्टें बदली। बाकी सब जस का तस। स्थाई और अस्थाई मज़दूरों में हलचलें बढने लगी तब यूनियन नेताओं ने मई-अन्त में कम्पनी पर दबाव डालने के लिये स्लो डाउन करने, उत्पादन कम करने को कहा। दस दिन बाद स्लो डाउन समाप्त करने को कहा। कम्पनी ने स्लो डाउन के दौरान ठेकेदार के जरिये 150 नये मज़दूर भर्ती कर उन से रात को 12 घण्टे की शिफ्टों में उत्पादन करवाया। अन्तत: अगस्त में यूनियन और मैनेजमेन्ट के बीच तीन वर्षीय समझौता हुआ। स्थाई मज़दूरों के वेतन में तीन वर्ष में 10000 रुपये की वृद्धि-4700, 2650, 2650 (अब तक वर्ष में 1500 से ज्यादा नहीं बढते थे)। अस्थाई मज़दूरों की तनखा में 3900 की वृद्धि-1300, 1300, 1300 (अब तक वर्ष में 500-1000 बढते थे)। हर वर्ष 35 को अस्थाई को स्थाई करना... इस-उस कुतर्क से 21 ही स्थाई किये। अस्थाई मज़दूरों में असंतोष लेकिन बहुत ज्यादा नहीं -नपिनो ऑटो की तरह यूनियन लीडरों को पिटने से बचने के लिये भागना नहीं पड़ा।

स्थाई और अस्थाई मज़दूरों में फ़र्क बढा। बाहर के तथा फैक्ट्री के यूनियन लीडरों की स्थाई मज़दूरों से दूरी बढी और कम्पनी से नजदीकी बढी। बन्द कमरों में योजना बनी और तैयारी हुई। ए-शिफ्ट छूटने के समय 1 नवम्बर को सब अस्थाई मज़दूरों, 310 मज़दूरों की नौकरी समाप्ति का नोटिस। एकमुश्त इतने मज़दूरों को निकालने की कम्पनी की हिम्मत यूनियन पर भरोसे पर आधारित थी। रविवार बाद, 3 नवम्बर को सब अस्थाई मज़दूर फैक्ट्री के बाहर और यूनियन के नेतृत्व में सब स्थाई मज़दूरों ने फैक्ट्री में काम करना जारी रखा। लेकिन अनगिनत चीज़ें हैं जिन्हें सरकारें और कम्पनियां भी अपने आंकलन में शामिल नहीं कर सकती। निकाले गये अस्थाई मज़दूरों का सम्पर्क-सम्बन्ध कुछ अति सक्रिय लोग़ों से था। श्रम विभाग में 3 नवम्बर को शिकायत और 4 नवम्बर से 60 पुरुष तथा 250 महिला मज़दूर फैक्ट्री के सामने बैठने लगे। अस्ती कम्पनी की योजना में यह एक फच्चर बना।

श्रम विभाग में तारीखें पड़ने लगी-11 नवम्बर, 14,17,20,24,27 नवम्बर, 1 दिसम्बर... कम्पनी 25 पुराने अस्थाई मज़दूरों को तोड़कर फैक्ट्री में ले गई और कुछ ने हिसाब भी ले लिया पर अधिकतर अस्थाई मज़दूर डटे रहे। कम्पनी ने एक महीने की नोटिस पे देने की बात की, श्रम अधिकारी ने 2-3 महीने की...

अस्ती के अस्थाई मज़दूरों ने 12 नवम्बर को मुंजालकिरियु फैक्ट्री के बाहर दो महीने से बैठे स्थाई मज़दूरों के साथ आई एम टी मानेसर में प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर 18 नवम्बर को अस्ती मज़दूरों ने अपना पर्चा बांटा और कई फैक्ट्रियों के यूनियन लीडरों से मिले। अस्ति फैक्ट्री के सामने 19 नवम्बर को गेट मीटिंग में कई यूनियन लीडरों ने खूब भाषण दिये। अस्ती यूनियन लीडर नहीं आये और उन्होंने 22 नवम्बर को साफ-साफ कह दिया कि वे कोई सहयोग नहीं कर सकते। दूसरी गेट मीटिंग 28 नवम्बर को और इसमें भी कई यूनियनों के लीडरों ने खूब भाषण दिये। अन्य के अलावा कुछ छात्र और युवा भी अस्ति के अस्थाई मज़दूरों को सहयोग देने और समर्थन जुटाने के लिये फैक्ट्री पहुंचे हैं, रात को भी साथ रहे हैं। श्रम विभाग में तारीखें, पर्चा-प्रदर्शन-मीटिंग में लीडरों के भाषणों से बात आगे नहीं बढती देख भूख हड़ताल करना तय हुआ। दो पुरुष तथा पांच महिला मज़दूरों ने 25 नवम्बर से अनिश्चतकालीन अनशन आरम्भ किया। समर्थन में हर रोज 5-10 अन्य लोग उनके साथ 24 घण्टे के अनशन पर बैठने लगे हैं। अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल पर बैठे 7 स्त्री-पुरुष मजदूरों का अनशन 5 दिसम्बर को जारी था...

श्रम विभाग में शिकायत। श्रम विभाग में तारीखें। प्रशासन को, सरकार को, अधिकारी को, विधायक-सांसद-मंत्री को ज्ञापन। पुलिस अनुमति से दस-बीस दिन में प्रदर्शन अथवा सभा। पर्चे-पोस्टर। धरना। भूख हड़ताल। इन सबका असर पड़ता है पर इनसे पड़ते प्रभाव को उल्लेखनीय मामलों में मज़दूरों ने बार-बार अपर्याप्त पाया है। ईमानदारी और बेईमानी की बातें यहां अर्थहीन हो जाती हैं।

न्याय के नाम पर अथवा मजबूरी में उठाये जाते कदम प्रस्थान-बिन्दू बन सकते हैं पर स्वयं में ये बहुत आगे नहीं जाते। यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि 3 अक्टूबर 2003 को मुम्बई में टाटा समूह की कम्पनियों के मुख्यालय, बॉम्बे हाउस के सामने टाटा पावर के स्थाई मज़दूरों में से दो ने, अनन्त दलवी और अख्तर खान ने आत्मदाह कर प्राण त्याग दिये थे। आज चीन में फैक्ट्रियों में ऊंचाई से कूद कर मज़दूर आत्महत्या करते हैं।

सार की बात मज़दूर-पक्ष है। मज़दूरों का मज़दूरों के पास जाना इस दिशा में पहला कदम है। अलग-थलग फैक्ट्रियों की जगह आज हज़ारों फैक्ट्रियों के अगल-बगल में होने ने इसे बहुत आसान बना दिया है। एक फैक्ट्री के मामले को एक हज़ार फैक्ट्रियों का मामला बनाना मज़दूर-पक्ष को ठोस आकार देने की दिशा में बढना है। औद्योगिक क्षेत्रों में आठ-दस ऐसे स्थान होते हैं जहां से अनेकों फैक्ट्रियों के दसियों हज़ार मज़दूर रोज़ आते-जाते हैं। अस्ति के बाहर किये अस्थाई मज़दूर हों चाहे मुंजाल किरियु के बाहर किये स्थाई मज़दूर, विशाल संख्या में मज़दूर के आने-जाने की राहों पर सुबह की शिफ्टों के आरम्भ होने के समय दो घण्टे बीस-तीस मज़दूरों द्वारा गत्तों पर अपनी बातें लिख कर एक दूसरे से बीस-तीस गज की दूरी पर खड़ा होना बहुत आसान है। इस से रोज ही एक फैक्ट्री के मज़दूरों की बातें हज़ारों फैक्ट्रियों में सहजता से होने लगती हैं। इस प्रकार सौ-दो सौ मज़दूरों का मामला हज़ार-दस हज़ार लाख मज़दूरों का मामला बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। फ़रीदाबाद में यह कारगर साबित हुआ है, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में यह कारगर रहा है। आइये, रंग-बिरंगे बिचौलियों के, ईमानदार-बेईमान बिचौलियों के पार चलें।